(6) The Border Area Development Programme and Border Road Programme will be extended to some more areas on the Indo- Myanmar border.

(7) A special cell will be set up in Reserve Bank of India to ensure improved credit flow.

(8) A new industrial policy for this region will be announced.

(9) An integrated tourism development Plan for the entire North-east region is being formulated.

(10) An export policy including border trade for NE region will be worked out.

(11) Railway services in the region will be imporved.

(12) Government have also decided to take up a number of important projects for implementation in different North-East States.

Fine on Foreign Ships Fishing in Indian Waters

2971. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether any fine has been imposed on the foreign ships found fishing in the Indian territoral waters during the last three years; and

(b) if so, the amount collected on this account?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) and (b) Information in being collected and will be placed on the Table of the House.

Supply of Natural Gas Through Pipeline in Gujarat

2972. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any scheme for utilisation of natural gas for domestic purposes and its distribution through pipeline in Ahmedabad and Saurashtra- Kutch region of Gujarat;

(b) whether the scheme is in operation in Vadodara and Surat;

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken to supply domestic gas to consumers, as in Vadodara and Surat; and

(d) if not, the difficulties being faced by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) No, Sir.

(b): Yes, Sir.

(c) and (d) As the gas projected to be available is fully allocated, it is not feasible to allocate gas for new projects at present.

Flaws in Panchayati Raj

2973. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to an article which appeared in the Indian Express dated the 8th November, 1996 about the "Flawed Panchayati Raj"; and

(b) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) and (b) Yes, Sir. It has been the endeavour of the Government of India to make the Panchayati Raj system more effective and responsive instruments for people's participation in local self-government.

डिग्बोई तेल शोध कारखाने में आग लगना

2974. **श्री राघवजी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में डिग्बोई तेल शोधक कारखाने में आग लगने की बहुत बड़ी घटना घटी है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) आग लगने से कुल कितनी वित्तीय क्षति हुई है;

(ग) आग लगने के क्या कारण पाये गये हैं; और

(घ) आग लगने से तेल शोधक कारखाने के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस कारखाने की पूर्व क्षमता को कब तक बहाल कर दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) डिग्बोई रिफाइनरी की वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में 30.11.1996 को आग लगने की एक घटना हुई। यह आग, रिसने वाले हाइड्रोकार्बनों के स्वजलन के कारण एक पंप (हैडलिंग हैवी वेक्सी डिस्टिलेट) की ड्रेन लाइन में एक गास्केट के काम न करने की वजह से लगी। ऐसा अनुमान है कि इस आग से 3800 टन क्रूड संसाधन के उत्पादन के नुकसान के अलावा क्षतिग्रस्त सामग्री को बदलने और उनकी मरम्मत की लागत पर लगभग 4.4 लाख रुपए की हानि हुई। यह यूनिट 4.12.96 से प्रचालनरत है।

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विद्युत उत्पादन संयंत्र

2975. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए 1995-96 तक कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) इन संयंत्रों की स्थापना के लिए अंतिम रूप से स्वीकृत स्थल कौन-कौन से हैं;

(ग) इन संयंत्रों की प्रस्तावित लागत कितनी है और इस राशि को प्राप्त करने की व्यवस्था किनके द्वारा किन ऐजेंसियों से की गई है अथवा की जानी प्रस्तावित है; और

(घ) इन संयंत्रों की शीघ्र स्थापना कर राज्य में विद्युत की कमी को दूर करने हेतु की जा रही कार्यवाही की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) चालू योजना अवधि के दौरान, 1995-96 तक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नयी ताप विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने संबंधी किसी भी प्रस्ताव को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। बस्तर जिले में बोधघाट जल विद्युत परियोजना (4x125 मेगावाट) को योजना आयोग द्वारा 24 फरवरी 1979 को 209.3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागतों पर स्वीकृत प्रदान कर दी गई थी। परियोजना पर निर्माण कार्य रोक दिए गए थे क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संबंधी स्वीकृति दिया जाना अस्वीकार कर दिया गया था।

(घ) राज्य की निम्नलिखित स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं द्वारा कमी को पूरा कर लिए जाने की प्रत्याशी हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम व स्थान	क्षमता (मेगावाट)
राज्य क्षेत्र परियोजनाएं		
1.	संजय गांधी विस्तार, टीपीपी यूनिट-3 और 4 बीरसिंहपर पाली (शहडोल) जिला 1	420
2.	बाणसागर टॉस फेस-2 (जिला रेवा)	30
3.	बाणसागर टॉस फेस-3 (जिला रेवा)	60
4.	बाणसागर टॉस फेस-4 (जिला सतना/शहडोल)	20
5.	नर्मदा सागर (इंदिरा सागर) (जिला खंडवा)	1000
निजी क्षेत्र परियोजनाएं		
1.	तावा एलबीसी (जिला होशंगाबाद)	12
2.	महेश्वर (खारगोन/खांडवा जिला)	400
संयुक्त क्षेत्र परियोजनाएं		
1.	राजघाट (म.प्र./उ.प्र.) (जिला गुणा, म.प्र., ललितपुर(उ.प्र.)	45
2.	सरदार सरोवर (म.प्र./गुजरात/महाराष्ट्र)	1450

इनके अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मरहीखेड़ा जल विद्युत परियोजना (2 x 20 मेगावाट) तथा जिला देवास/खांडवा में ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना (8 x 65 मेगावाट) स्थापित किए जाने के लिए अपनी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

Amendments in Gadgil Formula

2976. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have waived the Gadgil formula for distribution of ad-hoc Central assistance to States in the current year;

(b) if so, the criteria presently being followed by Government to disburse ad-hoc aid to States;

(c) whether the Gadgil formula would be amended for the Central Plans;

(d) if so, whether views of State Governments have been asked for by the Central Government; and

(e) if so, the reaction of State Governments thereto?